लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में समस्याएँ तथा समाधान : एक सैद्धान्तिक अध्ययन

ANJUL KUMAR, ANIL KUMAR

DEPARMENT OF MEDUAL AND MODERN HISTORY UNIVERSITY OF ALLAHABAD, D.PHIL Ist YEAR

प्रस्तावना–

शास्त्री जी से सम्बन्धित इतिहास लेखन के प्रायः दो दृष्टिकोण सामने आये हैं। एक वह जिसमें उन्हे भावातिरेक में आकर न्यायप्रिय किया जात रहा है तो दूसरा वह जो राजनीति में नेहरु–गाँधी परिवार की बादशाहत को अक्षुण्ण मानने के साथ शास्त्री जैसे अल्पकालिक प्रधानमंत्रियों को ''निर्णयहीनता का बंदी'' सिद्ध करता रहा है।[1]रामचन्द्र गुहा जैसे इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग भी है जो शास्त्री जी के सम्बन्ध में विचार करते समय कमोबेश तटस्थ रहा है। किन्तु प्रस्तुत शोधपत्र शास्त्री जी की राजनैतिक शख्सियत को कुछ सैद्धान्तिक आधारों के साथ प्रस्तुत करता है तथा यह शोधपत्र शास्त्री जी के व्यक्तित्व को भिन्न सिद्धान्तों का मिश्रण बहुआयामी सिद्ध करता है। बीते दिन दशकों से भारतीय राजनीति में विरासत की सियासत आम रही है तथा नेताओं, विचारकों, पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वोट बैंक बनाना आम बात है। वोट बैंक के इस सियासी दौर में गाँधी, नेहरु, पटेल, अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन्दिरा गाँधी, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, जय प्रकाश नरायण, काशीराम आदि महंगे शेयरों की तरह खरीदकर रख लिये गये हैं, ताकि विभिन्न वर्गो, समुदायों के वोट निश्चित लाभांश के रुप में प्राप्त किए जा सकें।

बिहार के चुनावी समर में प्रायः प्रत्येक दल स्वयं को जे0पी0 के परम्परा का वाहक बताता रहा है। ''क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र'' किन्तु शास्त्री जी राजनैतिक बाजारवाद से मृत्यु पश्चात औरों की बनस्पत दूर रहे कारण यह है कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व कोई ब्राण्ड नहीं जिसकी नुमाइश की जा सके, बल्कि वह तो जनमानस हेतु प्रेरणा की वह सरलीकृत, एवं विकेन्द्रीकृत संस्था है जिसकी आभा आज से व्यवस्था परिवर्तन करे तथा लोकतंत्रीकरण की अभिज्ञा तीव्र जाग्रत होती है।

इन पक्षों के अतिरिक्त शोधपत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि शास्त्री जी के नाम की राजनैतिक चर्चा न होने के पीछे कही यह कारण तो नहीं कि भारतीय अभिजन प्रधानमंत्री के पद को अमीरों की थाती मानता हो ? क्योंकि बकौल सुनील खिलनानी[2]''भारतीय अभिजन वर्ग कड़े नियंत्रण वाले शासन को अधिक पसंद करता है।'' (द आइडिया आफ इण्डिया)

परिचय–

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणराज्य के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद को अपनी प्रखर प्रतिभा से परिभाषित करने वाले शास्त्री जी की पारिवारिक विपन्नता सर्वज्ञातव्य हे, मुगलसराय वाराणसी में जन्मे शास्त्री जी का अध्ययनकाल भी मन को आह्लादित करने एवं जनमानस को सुषुप्तावस्था में भी प्रेरणा देने वाली एक करुण कथा है। मनस्वी, जिजीविषायुक्त शास्त्री जी को एक नदी पार कर अध्ययन करने हेतु काशी विद्यापीठ जाना पड़ता था। धनाभाव में नाव के चप्पू चलाने और तैर कर नदी पार करने की घटनाऐं उपरोक्त तथ्य को सतर्क प्रमाणित करती हैं। उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि की निर्मिति उस समय हुई जब भारतीय इतिहास का नवोन्नयनकारी वह दौर था जब स्वराज प्राप्त की अधुनातन प्रक्रिया के रुप में प्रखर सूर्य समान भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के तृतीय कालखंड का आरम्भ हुआ। इस वैचारिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त उनकी सुशिक्षित माँ द्वारा दिये पवित्र संस्कारों के आधार पर उन्होंने जनप्रेरणादायी आदर्श निश्चित किये। उनके उच्च गुणवत्तायुक्त मनुष्यों एवं आदर्शों का एक उदाहरण तब प्राप्त हुआ जब स्वतंत्र भारतीय राजनीति के प्रथम पुरोधा नेहरु की मृत्यु हुई (27 मई 1964) तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद हेतु जे0पी0 का नाम सुझाया। (बकौल कुलदीप नैयर)।[3]

1953 के बाद जे0पी0 के नेतृत्व में समाजवादियों और कांग्रेस में वैचारिक तीव्र हुये अैर 1957 के बाद जे0पी0 व नेहरू के व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी विच्छेदन दृष्टिगोचर होने लगी। ''आजादी के बाद भारत, बिपिन चन्द्रा।'' किन्तु उस समय शास्त्री दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशहित का विचार कर रहे थे। (रामबहादुर राय, ABP News 2013)[4]

नेहरु मंत्रिमण्डल में रेलमंत्री का पद केवल एक रेल दुर्घटना के कारण त्यागा और गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के वातानुकूलित कक्ष उन्हें अपनी ओर सम्मोहित कर पाने में सर्वथा विफल रहे। उनका जीवन गाँधी द्वारा अपनाए गये दर्शन, 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' का यथार्थ प्रमाण है।

उनके सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि वे अनेक बुर्जुवा कांग्रेसियों में सर्वहारा के एकमात्र सच्चे प्रतिनिधि थे तो यह उनके जीवन का सही मूल्याँकन होगा। पण्डित नेहरू ने उनके सम्बन्ध में एक बार कहा था कि ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण, ऊँचे आदर्शो में पूरी आस्था रखने वाले निरन्तर सजग व्यक्तित्व का नाम ही है लाल बहादुर शास्त्री किन्तु इतने पर भी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके प्रमुख आलोचकों जैसे 'विजयलक्ष्मी पण्डित' तथा बिपिन चन्द्रा जैसे इतिहासकारों ने उन्हे अनिर्णय के अवस्था का प्रतीक माना है। किन्तु प्रश्न है कि क्या उपरोक्त निर्मित का आधार निष्पक्ष विश्लेषण को बनाया गया है? यह आवश्यक है कि शास्त्री जी का निष्पक्ष एवं तटस्थ मूल्याँकन प्रस्तुत किया जाय।

शास्त्री की बौद्धिकता–

'एन्टोनियो ग्रामसी'[5] का मत है कि ''श्रमिक वर्ग को चाहिए कि वह अपने भीतर से समर्थक बुद्धिजीवी पैदा करे ऐसे बुद्धिजीवी जो समानान्तर संस्कृति को जन्म दे सके, कालान्तर में ये बुद्धिजीवी इस अवधारणा को कि मध्यवर्गीय जीवन मूल्य ही समाज के वास्तविक जीवन मूल्य है, को उखाड़ फेकेंगे। ''ग्रामसी के उपरोक्त बुद्धिजीवी होने का परिचय शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ प्रारम्भ होने के साथ ही दे दिया।

27 मई 1964 नेहरु के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के चयन का पक्ष उठना स्वभाविक था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उत्तराधिकारी के इस चयन प्रक्रिया के पूर्ण करने हेतु 'के कामराज' को नियोक्ता किया जो उस समय नेहरु गुट के प्रमुख समर्थक होने के साथ कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं (सिंडीकेट) के प्रमुख भी थे। कामराज की चुनौती यह थी कि कैसे बिना कांग्रेस को तोड़े नेहरु के उत्तराधिकारी की नियुक्ति किया जाय। उधर नेहरु कैबिनेट में मंत्री तथा संयुक्त

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मोरार जी भाई देसाई ने प्रधानमंत्री पद हेतु अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के साथ अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी। किन्तु शास्त्री के नेहरु मंत्रीमण्डल में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनने से देसाई तथा शास्त्री में प्रतिस्पर्द्धा स्वभाविक थी। शास्त्री जी ने उसी समय अपनी बुद्धियुक्त निर्णय क्षमता का परिचय दिया और कहा ''मैं सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के पक्ष में हूँ, फिर भी मैं देसाई से मुकाबला कर सकता हूँ।''[6](Indian Express तथा UNI 28 May 1964) उनकी इस निर्णय क्षमता ने विरोध के धार को कुन्द किया और शास्त्री निर्विवाद नेता बन सके।

कामराज से सम्बन्ध में राजनैतिक दक्षता का परिचय–

जार्ज एच सेबाइन[7] की उक्ति है– ''राजनैतिक सिद्धान्त राजनैतिक प्रक्रिया के एक भाग के रुप में विकसित होते हैं, और चूँकि इस प्रक्रिया का कोई अन्तिम अध्याय नही है इसलिए राजनैतिक सिद्धान्त का भी कोई अन्तिम अध्याय नहीं है।'' सेबाइन की इस उक्ति की स्पष्ट झलक शास्त्री कामराज सम्बन्धों में देखी जा सकती है। 2 जून 1964 को शास्त्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कार्यों का संचालन कैसे होगा इसके मानक कामराज ने एक भाषण में तय कर दिये थे, जिसमें उन्होंने कहा था–

''सामूहिक जिम्मेदारी व सामूहिक कोशिश ने सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जायेगी।''[8]इस प्रकार कामराज ने कांग्रेस दल का नियंत्रण सरकार पर बढ़ा दिया। लेकिन शास्त्री ने धैर्य धारण कर स्थिति को समझने का निर्णय लिया तथा मीडिया से केवल गरीबी को प्राथमिकता देने की बात कहीं।

यद्यपि सिंडीकेट तथा कामराज से शास्त्री से सम्बन्धों के आधार पर उन्हे एक कमजोर नेता समझा जाता रहा है, किन्तु सम्भवतः सिंडीकेट के दबाव को झेलने का कारण यह था कि यदि वे सिंडीकेट विरोधी रुख अपनाते तो सम्भवतः उन्हे अपना पद छोड़ना पड़ता।

शास्त्री तथा नेहरु परिवार में सम्बन्ध व राजनीति–

जीनजैक्स रूसो[9] ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धान्त (General will) में यह प्रतिपादित किया है कि– ''सामान्य इच्छा बहुमत व शक्ति से ऊपर है।'' तीन मूर्ति भवन के सम्बन्ध में उठे प्रश्न तथा शास्त्री द्वारा इसका समाधान करने में इस सैद्धान्तिक पक्ष के दर्शन होते हैं। तीन मूर्ति भवन वह स्थान था जहाँ पण्डित नेहरु रहा करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात इन्दिरा गाँधी और नेहरु की बहन कृष्णहथी सिंह ने अपने पत्रों के जरिये अपमानित करना शुरू किया, किन्तु शास्त्री ने बिना किसी प्रतिक्रिया के तीन मूर्ति भवन छोड़ने का निर्णय लिया। इस घटना को उनकी सद्इच्छा का प्रतीक न समझ उनकी कमजोरी माना जाता रहा है। यहाँ एक अन्य तथ्य की ओर संकेत कर देना भी आवश्यक है कि अगर वे ऐसा न करते तो सम्भवतः मंत्रिमण्डल में उनके प्रति विद्रोह बढ़ जाता इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था।

अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सुरक्षा व नीति–

चातुर्य–

प्रोफेसर रजनी कोठारी का मत है[10]''अगर आधुनिकीकरण हमारे समय की केन्द्रीय प्रवृत्ति है, तो उसकी चालक शक्ति है राजनीतिकरण लेकिन इसे नियंत्रित करने की कला मनुष्य अभी तक नहीं सीख पाया है। इसलिए वह आज भी घिसी पिटी समझदारी के शिकंजे में जकड़ा है।''

''राजनीति को नियंत्रित करने की कला'' जिस ओर प्रोफेसर कोठारी संकेत करते हैं शास्त्री जैसे विरले ही सीख पाने में सफल हुये हैं। शास्त्री सरकार के तीन माह ही बीते थे कि उनकी सरकार के विरुद्ध यह कहते हुये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि वे नेहरु की नीतियों से हट रहे हैं।

अखिल भारतीय जनसंघ ? किन्तु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। यह उनकी निर्णयन क्षमता तथा राजनीति को नियंत्रित करने की कला ही थी कि उन्होंने अपने सांसदों का संगठित समुच्चय बनाये रखा और अपनी सरकार बचा लिया।

खाद्य संकट का निपटारा–

P.V. Rajeev ने अपनी पुस्तक[11]''वैश्वीकरण के युग में भारत'' में एक परिकल्पित कृषि माडल प्रस्तुत किया जिसके चार तत्व खाद्य सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं।

(i) घरेलू स्तर पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि

(ii) अन्तराष्ट्रीय खाद्यान्न व्यापार में सीमित दखल।

(iii) देश के भीतर क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा का सुरक्षित किया जाना।

(iv) सुरक्षित भण्डार के जरिये खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखा जाना।

उपरोक्त तत्वों की प्राथमिक पिठिका शास्त्री जी के खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीतियों में देखी जा सकती है। जहाँ एक ओर विरोधी दलों की आलोचना थी, वहीं 1964–65 में भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। उपरोक्त परिस्थितियों में शास्त्री ने अपनी कार्यविधि में परिवर्तन किया और देश को आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादक बनाने हेतु एक बड़ा संकल्प करते हुये भारतीय जन को हफ्ते में एक दिन के उपवास का नारा दिया। उनका यह निर्णय पूर्णतः प्रायोगिक था, क्यूँकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में खेती कर किचन गार्डेन की परम्परा प्रारम्भ किया। तब के इलाहाबाद (प्रयागराज) में उन्होंने किसानों के मध्य जय जवान, जय किसान का नारा देकर उन्हे कृषि कर्म हेतु प्रेरित किया।

P.J. Kurian की मदद से दुग्ध उत्पादन की नयी योजनाऐं प्रारम्भ की तथा अन्न भंडार संचरण हेतु खाद्य संरक्षण के नीतियों में परिवर्तन किये। अमेरिकी निर्भरता को समाप्त कर आयात कम करने के प्रयत्न किये। अतः स्पष्ट हो गया कि शास्त्री का कृषि मॉडल खाद्य सुरक्षा की आधारशिला बनी। जिससे खाद्य संकट समाप्त हो सका।

भारत पाकिस्तान युद्ध तथा शास्त्री जी की निर्णायक भूमिका 1965–

प्रो0 E.H. कार का कथन है कि ''प्रायः मूर्ख अपनी गलतियों से सीखता है और विद्वान दूसरो की।'' जहाँ एक ओर आर्थिक कमजोर और अकाल आर्थिक स्थिति थी

वहीं 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया यह वह दौर था जब भारतीय सेना का मनोबल चीन की हार से पस्त हो चुका था इन्ही परिस्थितियों में पाकिस्तान ने भारत के कच्छ क्षेत्र की विवादित सीमा कंजरकोट पर कब्जा कर लिया और अन्तराष्ट्रीय दबाव के कारण शास्त्री ने पाकिस्तान से समझौता किया जिसके तहत 75 Square Meal भूमि भारत ने पाकिस्तान को दी। कच्छ का समझौता शास्त्री जी द्वारा लड़ाई को टालने की नीति का एक हिस्सा था।

किंतु 5 अगस्त 1965 तक शास्त्री ने युद्ध की अनिवार्यता को समझ लिया। पाकिस्तानी नेता अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो का यह अनुमान था कि निर्णय लेने में समर्थ नही है और यह कश्मीर को हथिया लेने का अच्छा अवसर था पाकिस्तानी नेताओं की इसी मनोवृत्ति के तहत 2 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान ने छंद सेक्टर में आपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत भारतीय सेना पर आक्रमण किया।

अब शास्त्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए वायुसेना के प्रयोग की अनुमति दी यद्यपि इस योजना में पर्याप्त जोखिम या किन्तु भारतीय सेना की रण कुशलता तथा शास्त्री की निर्णयन प्रतिभा द्वारा पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेल दिया गया। यही नही शास्त्री जी ने जम्मू–कश्मीर को बचाने के लिए जनरल के एन. चौधरी को पंजाब की ओर से मोर्चा खोलने की अनुमति प्रदान की फलतः भारतीय सेना ने विजय को प्राप्त किया। यदि शास्त्री जी द्वारा अन्तराष्ट्रीय सीमा को खोलने का न लिया गया होता तो सम्भव था कि भारत का स्वर्ग कश्मीर भारत के हाथों से निकल जाता। इन सब के अतिरिक्त शास्त्री जी ने युद्ध पश्चात भारतीय सेना का उत्साहवर्द्धन करना जारी रखा उन्होने अपने एक भाषण में भारतीय सेना के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुऐ कहा था कि ''जिस मजबूती के साथ जम्मू बार्डर पर हमारी फौज के लोगों ने काम किया है मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ वे और मजबूती से हमारे फ्रण्टियरर्स की जिस तरह से सेवा, खिदमत, रक्षा कर सकें करें।

उनके इस निर्णय ने न केवल इतिहास को एक मोड़ दिया बल्कि प्रो० जोशी (इलाहाबाद वि०वि० के मध्यकालीन विभाग) की इस बात की पुष्टि की कर दी की विपरीत धारा में बहकर नदी पार करना ही जीवन है। लाहौर पर कब्जा न करना भी

उनका एक बड़ा निर्णय था जिसके पीछे कुछ हद तक भारत की आर्थिक दशा भी उत्तरदायी थी उपरोक्त घटना ने प्रो० कार की उपरि लिखित उक्ति को सत्य सिद्ध करने के साथ, माओत्सेतुंग के दर्शन "संघर्ष, समझौता, संघर्ष" के सकारात्मक पक्षो की ग्राहयता की पुष्टी भी की।

कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण–

लेनिन की यह युक्ति की राज्य वर्ग संघर्षो की असाध्यता की उपज है लोकतंत्र में भी प्रभावी रही है। जिससे प्रधानमंत्री की कैबिनेट तक पर भी असर पड़ा है।

भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात शास्त्री ने अपने कैबिनेट मे उपस्थित हो रहे संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया।

उनके प्रधानमंत्रित्व काल के प्रारंम्भ से ही कई मंत्री उनकी अवमानना करते रहे थे जिनमे टी.टी. कृष्णामचारी और इंदिरा गांधी प्रमुख थे कृष्णामचरी पर लगे आरोपों के जाँच के प्रश्न पर उन्होनें त्याग पत्र दे दिया व इंदिरा गाँधी को राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजने पर भी सहमती बन गयी। इन निर्णयो का अभिप्राय यह था कि वे राजनीति मे परिपक्यता का प्रदर्शन करते हुए बड़े निर्णय लेने लगे थे।

इन सबका अभिप्राय यह था कि अब वे "राजनीति को नियंत्रित करने की कला" प्रो० रजनी कोठारी सीख चुके थे।

ताशकन्द समझौता तथा शास्त्री जी की अन्तराष्ट्रीय समझ–

बर्टन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों मे बिनिर्णयन तथा विनिश्चयन के लिए तीन चीजो पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1. आभास 2. अपेक्षा और 3. जानकारी की प्रचुरता अर्थात परिवेश और परिस्थिति की समाझ तथा विषयों की जानकारी "प्रो० पुष्पेश पंत–ईक्कीसवी सदी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध"।

ताशकंद समझौता इन्ही सिद्धातों पर आधारित है। जनवरी 1966 में ताशबन्द में सोवियत रूप की मध्यस्थता के अन्तर्गत भारत पाक बैठक आरम्भ हुई और 11 जनवरी 1966 को सीज फायर सीमा पर वापस जाने व अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति बनाये

रखने के साथ अन्राष्ट्रीय मध्यस्ता से झगड़ो के निपटाने की शर्तो पर संधि हुई। सीमा से सेना की वापसी का अर्थ था भारत का बढ़तका कम हो जाना किन्तु इतने पर भी ताशकन्द समझौता अभी अन्तर्राष्ट्रीय समझ का परिणाम था। क्योंकि वे शीत युद्ध को भारत की द्वार पर नही लाना चाहते थे। यदि वह ऐसा न करते तो सम्भवतः अमेरिका पाकिस्तान की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता। ताशकन्द समझौते की इसी सफलता को ध्यान में रखकर अली सरदार जाफरी ने अपनी एक नज्म शास्त्री जी को सर्मपित की–

''मनाओ जश्न–ए– मोहब्बत के खून की बू न रही,

बरस के खुल गये बारूद के सियाह बादल।

बुझी–बुझी सी है जंगो की अखिरी बिजली,

महक रही है गुलाबों से ताशकन्द की शाम।

खुदा करें की शबनम यूँ ही बरसती रहे,

जमीं हमेशा लहू के लिये तरसती रहें।।''

संविधान में भाषा के प्रश्न का निराकरण व शास्त्री जी द्वारा राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा–

प्रो० अमर्त्यसेन का कथन है कि "स्वीकार और समावेश के उपहारों में बहिष्कार के कठिन दंड भी पहचान भावना के साथ चलते है।

"बिना और अस्मिता का संकट"। इसी पहचान भावना ने 1965 में भाषा के प्रश्न पर दक्षिण भारतीय राज्यों में संघर्ष मूलक परिस्थिति उत्पन्न हुई। दरअसल 1950 में भारतीय संविधान में गैर भाषी राज्यों के लिए संवैधानिक कार्यहेतु अंग्रेजी भाषा की नियुक्ति की गई थी। 1965 में इसकी कालावधी पूरी होने के साथ ही जब एक ओर सम्पूर्ण भारत में हिन्दी को मातृभाषा का दर्जा देने का अभियान शुरू हुआ तो दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे। ऐसे मे शास्त्री जी ने न केवल अंग्रेजी भाषा का दर्जा बनाये रखा बल्कि कुछ अन्य भाषाओं को संविधान में स्थान

दिया। अतः उनकी समझ को अमर्त्यसेन के शब्दों मे कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है "अपने ऊपर पहचान की उस भावना जिसमे सांस्कृतिक समरूपता निहितहोती है से केवल खुशी और गर्व ही हासिल नही होता बल्कि अपने ऊपर विश्वास भी मिलता है। जिससे ताकत प्राप्त होती है।

वर्तमान भारतीय राजनेताओं द्वारा शास्त्री जी की राजनीतिक शख्सियत का सकारण व्याख्या।

वर्तमान समय मे भारतीय राजनीति आदर्शप्रेम केन्द्र न होकर कौअिल्य द्वारा सुझाए गए, साम, दाम, दंड, भेद के सिद्धान्त पर आधारित हो गयी है। तथा इसका प्रतिबिम्ब "तीन बुलावै तेरह आवै" सा प्रतीत होने लगा है। ऐसे में तुच्छ गुणवत्तायुक्त मूल्यों को धारण करने वाले पूर्व राजनेता वर्तमान राजनेताओं के वोटबैंक निर्माण में लिये गये बैंक लोन पर अधिकतम ब्याज के समान प्रतीत हुये है। और चूँकि शास्त्री जी उन्ही गुणवत्ता युक्त मूल्यों के प्रतिनिधित्व करते थे अतः उनकी अवहेलना बहुत स्वावभाविक है।

दूसरे वर्तमान समय में ताकतवर छवि के नेता आदर्शस्वरूप समझे जाने लगें। ऐसे में किसी भी लोकतंत्र की पुरोधा की अवहेलना राजनीतिक बाजारवाद के इस दौर में सम्भव है।

अस्मिता की राजनीति की इस दौर में प्रायः वे नेता चर्चा में रहे है। जिनकी छवि किसी जाति विशेष अथवा वर्ग विशेष का चुनावी समर्थन दिलाने में समर्थ हो और चूँकि शास्त्री जी इनमे से किसी एक का भी प्रतिनिधित्व नही करते थे सम्भवतः इसीलिए वर्तमान जन को उनकी चर्चा गैर वाजिब प्रतीत होती है। ऐसे में विद्युत चक्रवर्ती की "शक्ति संरचना आधारित राजनीति की अवधारणा सत्य सिद्ध हुई हैं।

निष्कर्ष—शास्त्री जी अपने समकालीन नेताओं में किसी भी तरह कम लोकप्रिय न थे। इसका एक प्रमाण तब प्राप्त हुआ जब उन्होने 1957 में तब की इलाहाबाद सीट से 58%मत प्राप्त कर चुनावी विजय प्राप्त की "हिन्दुस्तान 13 मार्च 2019" उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उनके 18 महीने के शासनकाल में देश ने अनेको

उपलब्धियाँ प्राप्त की और प्रगति की नीव का निर्माण किया। वी0पी दत्त ने अपनी पुस्तक 'स्वातन्त्र भारत की विदेश नीति' में उचित टिप्पणी की है कि– ''नर्म व्यहार, नाटा कद और किसी बाहरी आकर्षण से रहित उन्होने धीरज और नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया।'' किसी व्यक्ति की सफलता का एक पैमाना यह भी है कि उसका धुर विरोधी उसकी प्रशंसा करे। शास्त्री जी के धुर विरोधी अयूब खान ने शास्त्री जी की मृत्यु पर शोक संदेश देते हुए कहा था '' Here lise the person who could have brougt India and Pakistan together." किन्तु प्रायः उनका विश्लेषण करने वालो मे विपिन चन्द्र जैसे इतिहासकारों में Oscar Wilde की उस उचित कथन को अपने लेखन का आधार बनाया है कि जिसमे उन्होने कहा था कि "प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के विचार किसी अन्य के विचार होते है। अतः स्पष्ट है कि शास्त्री जी की निर्णयन शक्ति पर दोषारोपण इतिहास लेखन मे पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति को सिद्ध करता है।

का मूल्यांकन उ0प्र0 दत्त लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी किताब यधपि उनसे कुछ भूले होने की सम्भावनाएँ भी थी किन्तु उनके विश्लेषण में तैरकर पार सरत के पारसन्स पैटर्न की अवधारणा को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिसमे उन्होने कहा था "प्रत्येक व्यक्ति निर्णय लेते समय झिझक का अनुभव करता है। और चूँकि शास्त्रीजी प्रधानमंत्री के साथ–साथ एक व्यक्ति भी अतः उनका भूल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. क्षेत्रिय व राष्ट्रीय दलों के घोषणापत्र, (2013–2018)
2. खिलनानी, सुनिल, द ऑइडिया ऑफ इण्डिया।
3. चन्द्र विपिन, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, (2009) आजादी के बाद भारत, (269) 4th edition, हिन्दी माध्यम कार्यांचयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
4. रामबहादुर राय, 2013, ABP News
5. शास्त्री अनिल व पवन चौधरी 2014 लेसन्स इन लीडरशीप (विज्डम विलेज पब्लिकेशन)

6. कश्यप ओम प्रकाश, (2016), एन्टोनियो ग्राम सी और उसका संस्कृतिक आधित्यवाद (p-22), शोध गंगा, ज्ञान गंगा।
7. Indian Express and UNI, (28-30 May, 1964)
8. Sabine H george (1973), History of Palitical theory, 1st editio, Qxford university press.
9. डा० अरोड़ा एन०डी० (1998), आधुनिक राजनीतिक विचारक (p-77), हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
10. प्रो० कोठारी रजनी (2005), भारत मे राजनीति कल और आज, (p-22), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. राजीव, पी०वी०, बैश्विकरण के यूग मे भारत, (2007), (p-30), राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
12. कार ई० एच०, व्हाट इज हिस्ट्री, (p-105)
13. लेनिन, वी०आई०, राज्य और क्राँति (p-B), राहुल फॉउडेशन, पेपरमील रोड, लखनऊ।
14. प्रो० पंत पुष्पेश, (2007), 21 वीं शताब्दी में अन्तराष्ट्रीय संबद्ध (p-83), टाटा मैग्राहिल कं० नई दिल्ली।
15. सेन अमर्त्य (2004), हिरा और अस्मिता का संकट, (p-19), राजस्थान एण्ड सन्स नई दिल्ली (वही पेज–20)
16. दत्त वी0पी0, स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति 2009 पेज नं0 25 नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन।